लोक सभा

अतारांकित प्रश्नर संख्यान1003

02 मार्च, 2015 को उत्तलर के लिए

इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की कमी

1003. डॉ. शशि थरूर:
श्री रवनीत सिंह:
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:
श्री देवुसिंह चौहान:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात क्षेत्र कच्चे माल जैसे कि लौह अयस्क और कोयला की भारी कमी से जूझ रहा है और इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ते आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खनन विकास निगम द्वारा घरेलू इस्पात क्षेत्र को लौह अयस्क की कितनी मात्रा आपूर्ति की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर और उन मुद्दों को सुलझाकर जिस कारण ओडिशा कर्नाटक और झारखंड में खनन कार्यों पर रोक लगायी गई, को देखते हुए घरेलू इस्पात क्षेत्र को उक्त कच्चेमाल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं ?

उत्त/र

इस्पांत और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णुि देव साय**

(क) और (ख): जी नहीं। लौह अयस्क जैसे कच्चे माल की अत्यधिक कमी नहीं है। तथापि, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के निरस्तीकरण तथा गोवा और ओड़िशा राज्यों में लीज नवीनीकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की वजह से लौह अयस्क की क्षेत्रीय कमी हुई है। लौह अयस्क का आयात वर्ष 2013-14 में 0.37 मिलियन टन(एमटी) से बढ़कर वर्ष 2014-15 (अप्रैल-नवम्बर) मे 5.63 एमटी हो गया है। भारत में कोकिंग कोल, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण में होता है, का अधिकांशत: आयात इसकी अनुपलब्धता कम होने के कारण किया जाता है।

(ग): गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा घरेलू क्षेत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति की गई मात्रा निम्नवत है:-

मात्रा मिलियन टन में

वर्ष	**उत्पा दन**	**घरेलू इस्पा त क्षेत्र को की गई लौह अयस्क की आपूर्ति**
2011-12	27.3	26.91
2012-13	27.0	24.67
2013-14	30.2	28.2
2014-15 (**अप्रैल**'14 – **जनवरी**'15)	25.63	23.34

(घ): भारत सरकार ने खनन कार्यों में तेजी लाने के लिए द कोल माईन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) ऑर्डिनेन्स, 2014 और द माईन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन्स), 2015 लागू किए हैं। कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति से संबंधित चिंताओं का भी समाधान राज्य सरकारों के साथ आईएमजी की बैठकों में किए जाते हैं।

*****